



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]

नई दिल्ली, रविवार, जनवरी 1, 1995/पाँच 11, 1916

No. 1]

NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 1, 1995/PAUSA 11, 1916

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना नं. 2/85 (सी.शु.)

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1995

सा.का.नि. 1(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमानुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (6) और धारा 9ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमानुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का प्रवधारण) नियम 1985 की उन बातों के सिवाय अधिभक्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमानुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का प्रवधारण) नियम, 1995 है।

(2) ये 1 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से सीमानुल्क टैरिफ-अधिनियम, 1975 (1975 का 51) अभिप्रेत है;

(ख) “घरेलू उपयोग” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

वैसी ही वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन और उससे संबद्ध किसी क्रियाकलाप में लगे हुए समस्त घरेलू उत्पादक या वे घरेलू उत्पादक जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन, उस वस्तु के घरेलू उत्पादन का एक पर्याप्त भाग तब के सिवाय बनता है जब ऐसे उत्पादक अभिकषित पाटित वस्तु के निर्यात-कर्ताओं या आयातकर्ताओं के नातेदार हैं या वे स्वयं उसके आयातकर्ता हैं। ऐसी दशा में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं समझा जाएगा:

परन्तु नियम 11 के उपनियम (3) में निविष्ट असाधारण परिस्थितियों में, प्रशस्त वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग में या अधिक प्रतियोगी बाजार समाविष्ट समझे जाएंगे और ऐसे

प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादकों को एक अलग उद्योग समझा जाएगा, यदि—

(1) ऐसे किसी बाजार के भीतर उत्पादक प्रथमतः वस्तु का अपने, सभी या लगभग सभी उत्पादन का उस बाजार में विक्रय करते हैं, और

(2) उस बाजार मांग की, राज्य क्षेत्र में अन्यत्र अवस्थित उक्त वस्तु के उत्पादकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं की जाती है;

(ग) "हितबद्ध पक्षकार" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

(1) किसी ऐसी वस्तु का जो भारत में पाटन किए जाने के लिए अन्वेषण के अधीन है, कोई निर्यातकर्ता या विदेशी उत्पादक या उसका आयातकर्ता या किसी व्यापार या कारबार संगम जिसके बहुसंख्यक सदस्य ऐसी वस्तु के उत्पादक, निर्यातकर्ता या आयातकर्ता हैं;

(2) निर्यात करने वाले देश की सरकार; और

(3) भारत में वैसी ही वस्तु का कोई उत्पादक या कोई व्यापार और कारबार संगम जिसके बहुसंख्यक सदस्य वैसी ही वस्तुएं भारत में उत्पादित करते हैं;

(घ) "वैसी ही वस्तु" से ऐसी कोई वस्तु अभिप्रेत है जो समरूप है, या सभी बातों में भारत में पाटन किए जाने के लिए अन्वेषण के अधीन वस्तु के समरूप है या वैसी ही किसी वस्तु के अभाव में, ऐसी दूसरी वस्तु के समरूप है, जो यद्यपि सभी बातों में समरूप नहीं है फिर भी उसमें ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्वेषण के अधीन वस्तु की विशेषताओं के प्रति सदृश हैं;

(ङ) "अन्ततिम शुल्क" से अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित प्रतिपादन शुल्क अभिप्रेत हैं;

(च) "विनिर्दिष्ट देश" से ऐसा देश या राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और उसके अंतर्गत वह देश या राज्यक्षेत्र है जिसके साथ भारत सरकार का सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्रीय व्यवहार प्रदान करने के लिए करार किया है।

(छ) ऐसे सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3. अभिहित प्राधिकारी की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति में नीचे का न हो या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे वह सरकार ठीक समझे, इन नियमों के प्रयोजन के लिए अभिहित प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है।

(2) केन्द्रीय सरकार अभिहित प्राधिकारी को ऐसे अन्य व्यक्तियों की सेवाएं और ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है जो वह ठीक समझे।

4. अभिहित प्राधिकारी के कर्तव्य—(1) अभिहित प्राधिकारी का इन नियमों के अनुसार निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :—

(क) किसी वस्तु के आयात के संबंध में किसी अभिकथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव के बारे में अन्वेषण करना;

(ख) ऐसी वस्तुओं की पहचान करना जो पाटन विरोधी शुल्क की दायी हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित के बारे में अपना अन्ततिम या अन्यथा निष्कर्ष प्रस्तुत करना—

(1) अन्वेषणाधीन वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन का माजिन; और

(2) विनिर्दिष्ट देश से ऐसी वस्तु के आयात के परिणामस्वरूप भारत में स्थापित किसी उद्योग को क्षति या क्षति की धमकी या भारत में किसी उद्योग के स्थापन तात्त्विक गतिरोध।

(घ) पारन विरोधी शुल्क की मात्रा की सिफारिश जो यदि उद्गृहीत की जाएगी तो देशी उद्योग का क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी और ऐसे शुल्क के प्रारम्भ की सारोख की सिफारिश करना, और

(ङ) पाटन विरोधी शुल्क के जारी रखे जाने के आवश्यकता का पुनर्विचिन्तन करना।

5. अन्वेषण का शुरु किया जाना;—(1) उपनियम (4) में यथा उपबंधित के सिवाय, अभिहित प्राधिकारी केवल घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किसी लिखित आवेदन की प्राप्ति पर किसी अभिकथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और उसके प्रभाव को अवधारित करने के लिए अन्वेषण शुरू करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन उस प्रकृति में होगा जो अभिहित प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे और आवेदन निम्नलिखित साक्ष्य द्वारा समर्थित होगा :—

(क) पाटन,

(ख) क्षति जहां लागू हो, और

(ग) जहां लागू हो, वहां ऐसे पारित आयातों और अभिकथित क्षति के बीच प्राकस्मिक संबंध;

(3) अभिहित प्राधिकारी उप-नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन के अनुसरण में तब तक अन्वेषण शुरू नहीं करेगा जब तक कि—

(क) वह ऐसे ही वस्तु के घरेलू उत्पादकों द्वारा व्यक्त आवेदन के लिए या उसके विरुद्ध समर्थन की मात्रा की जांच के आधार पर यह अवधारित नहीं करता कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उद्योगों से किया गया है;

परन्तु कोई अन्वेषण शुरू नहीं किया जाएगा, यदि आवेदन का अभिव्यक्ततः समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादक, घरेलू उद्योग द्वारा वैसे ही वस्तु के कुल उत्पादन के पचीस प्रतिशत से कम का लेखा देते हैं, और

(ख) वह आवेदन में दिए गए साक्ष्य की समुचितता और पर्याप्तता की परीक्षा और श्रुति यह समाधान नहीं कर लेता है कि किसी अन्वेषण के शुरू किए जाने को न्यायोचित ठहराने के लिए उसके पास—

(1) पाटन का,

(2) क्षति का, जहां लागू हो, और

(3) जहां लागू हों, वहां ऐसे पाटित आयातों और अभिकक्षित क्षति के बीच किसी आकस्मिक संबंध का,

पर्याप्त साक्ष्य है।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन के लिए, आवेदन घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर से किया गया समझा जाएगा, यदि आवेदन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है जिनका सामूहिक उत्पादन आवेदन के प्रति समर्थन या विरोध प्रकट करते हुए घरेलू उद्योग के उम्र भाग द्वारा उत्पादित वैसे ही वस्तु के कुल उत्पादन का पचास प्रतिशत से अधिक है।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, अभिहित प्राधिकारी कोई अन्वेषण स्वप्रेरणा से शुरू कर सकेगा यदि उसका सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन नियुक्त सीमाशुल्क कलक्टर से या किसी अन्य स्रोत में प्राप्त जानकारी से यह समाधान हो जाता है कि उपनियम (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिस्थितियों की विद्यमानता के बारे में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है।

(5) अभिहित प्राधिकारी कोई अन्वेषण शुरू करने से पूर्व निर्यात करने वाले देश की सरकार को अधिसूचित करेगा।

6. अन्वेषणों को शास्तित करने वाले सिद्धान्त :—(1) अभिहित प्राधिकारी किसी वस्तु के अभिकक्षित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का अवधारण करने के लिए कोई अन्वेषण शुरू करने के विनिश्चय के पश्चात् अपना विनिश्चय अधिसूचित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी

करेगा और ऐसी सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के बारे में निम्नलिखित सूचना होगी :—

(1) निर्यात करने वाले देश का नाम या वे देश और अस्तर्ध्वलित वस्तु;

(2) अन्वेषण शुरू किए जाने की तारीख;

(3) वह आधार, जिस पर आवेदन में पाटन अभिकक्षित है;

(4) उन कारणों का सारांश जिन पर क्षति का अभिकथन आधारित है;

(5) वह पता जिस पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदन भेजे जाएं; और

(6) हितबद्ध पक्षकारों को उनके दृष्टिकोण की जानकारी के लिए अनुज्ञात समय सीमा।

(2) सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अभिहित प्राधिकारी द्वारा पाटित की गयी अभिकक्षित वस्तु के ज्ञात निर्यातकर्ताओं, निर्यात करने वाले देशों की सम्बद्ध सरकारों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अप्रेषित की जाएगी।

(3) अभिहित प्राधिकारी, नियम 5 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आवेदन की एक प्रति—

(1) ज्ञात निर्यातकर्ताओं या वे सम्बद्ध व्यापार संगम को जब निर्यातकर्ताओं की संख्या अधिक हो; और

(2) निर्यात करने वाले देशों की सरकारों को; परन्तु वह आवेदन भी एक प्रति लिखित अनुरोध पर किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार को भी उपलब्ध कराएगा।

(4) अभिहित प्राधिकारी, निर्यातकर्ताओं, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से ऐसे प्रश्न में जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी जानकारी की अपेक्षा करने वाली सूचना जारी कर सकेगा और ऐसे व्यक्तियों द्वारा सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गयी अवधि के भीतर जिसे पर्याप्त कारण उपदर्शित किए जाने पर अभिहित प्राधिकारी अनुज्ञात करे, लिखित रूप में ऐसी जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए जानकारी और अन्य दस्तावेजों की अपेक्षा करने वाली सूचना उस तारीख से जिसको वह अभिहित प्राधिकारी द्वारा निर्यात करने वाले देश के समुचित राजनयिक प्रतिनिधि को भेजी गयी थी या संप्रेषित की गयी थी, एक सप्ताह के भीतर प्राप्त की गयी समझी जाएगी।

(5) अभिहित प्राधिकारी, अन्वेषण के अधीन वस्तु के औद्योगिक उपयोक्ताओं और जहां वस्तु फुटकर स्तर पर समान रूप से विक्रीत की जाती है वहां प्रतिनिधि उपयोक्ता

संगठनों को ऐसी जानकारी देने का अवसर प्रदान करेगा जो पाटन, क्षति, और जहां लागू हो वहां कारण की बाबत अन्वेषण के लिए सुसंभत है।

(6) अभिहित प्राधिकारी अन्वेषण से सुसंगत जानकारी मौखिक रूप से देने के लिए किसी हितवद्ध पक्षकार या उसके प्रतिनिधि को अनुज्ञात करेगा किन्तु ऐसी मौखिक जानकारी पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा तब विचार किया जाएगा जब यह लिखित रूप में तत्पश्चात् पुनः प्रस्तुत की जाए।

(7) अभिहित प्राधिकारी एक हितवद्ध पक्षकार द्वारा उसे दिए गए माध्यम को अन्वेषण में भाग ले रहे अन्य हितवद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराएगा।

(8) उस मामले में जहां कोई हितवद्ध पक्षकार युक्तियुक्त कालावधि के भीतर आवश्यक जानकारी के लिए पहुंच से इंकार करता है, या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या अन्वेषण में अत्यधिक अड़चन डालता है, वहां अभिहित प्राधिकारी उसको उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें करेगा जो वह ऐसी परिस्थितियों के अधीन ठीक समझे।

7. गोपनीय जानकारी—(1) नियम 6 के उपनियम (2), (3) और उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4), और नियम 17 के उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त किए गए आदेशों की प्रतियां या अन्वेषण के अनुक्रम में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीयता के आधार पर अभिहित प्राधिकारी को दी गयी कोई अन्य जानकारी, अभिहित प्राधिकारी का उसकी गोपनीयता के बारे में समाधान हो जाने पर, उसके द्वारा उसे गोपनीय माना जाएगा और ऐसी कोई जानकारी, ऐसी जानकारी देने वाले उस पक्षकार के विनिर्दिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) अभिहित प्राधिकारी, गोपनीय आधार पर जानकारी देने वाले पक्षकारों से गोपनीय जानकारी के तार को समुचित रूप से जानने के लिए उसका अगोपनीय संक्षेप पर्याप्त रूप से सविस्तार देने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि, ऐसी जानकारी देने वाले किसी पक्षकार की राय में, ऐसी जानकारी का संक्षेप नहीं बताया जा सकता है तो ऐसा पक्षकार अभिहित प्राधिकारी को ऐसे कारणों का एक कथन प्रस्तुत कर सकेगा कि उसका संक्षेप तैयार करना क्यों संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि अभिहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध अपेक्षित नहीं है या जानकारी देने वाला जानकारी को सर्वविदित करने या साधारण या संक्षिप्त रूप में उसका प्रकटन प्राधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी जानकारी की अपेक्षा कर सकेगा।

8. जानकारी की यथार्थता—नियम 6 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट मामलों के सिवाय, अभिहित प्राधिकारी अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी की यथार्थता के बारे में अपना समाधान करेगा, जिस पर इसके निष्कर्ष आधारित हैं।

9. अन्य विनिर्दिष्ट देशों के राज्यक्षेत्र में अन्वेषण: अभिहित प्राधिकारी दी गयी जानकारी सत्यापित करने या और ध्यौरे प्राप्त करने के लिए किन्हीं अन्य देशों के राज्य क्षेत्र में अन्वेषण कर सकेगा:

परन्तु यह तब जब कि अभिहित प्राधिकारी संबंध व्यक्ति की सहमति अभिप्राप्त कर लेता है और संबंध सरकार के प्रतिनिधियों को अधिसूचित कर देता है और संबंध सरकार ऐसे अन्वेषण पर कोई आक्षेप नहीं करती है।

10. पाटन के सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और अंतर का अवधारण—(i) कोई वस्तु पाटित की गयी तब मानी जाएगी जब उसका निर्यात किसी एक देश या राज्यक्षेत्र से भारत को उसके सामान्य पाटन मूल्य में कम कीमत पर किया जाता है और ऐसी परिस्थितियों में, अभिहित प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ इन नियमों के उपाबंध (1) में अधिकृत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पाटन के सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और अंतर का अवधारण करेगा।

11. क्षति का अवधारण—(1) विनिर्दिष्ट देशों से आयातों के मामले में अभिहित प्राधिकारी यह निष्कर्ष और अभिलिखित करेगा कि ऐसी वस्तु का भारत में आयात किए जाने से भारत में स्थापित किसी उद्योग को तात्त्विक क्षति पहुंचती है या उससे भारत में किसी उद्योग की स्थापना का तात्त्विक गतिरोध उत्पन्न होता है।

(2) अभिहित प्राधिकारी, उन सभी सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिनके अंतर्गत पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में वैसी ही वस्तुओं के लिए कीमत पर उनका प्रभाव और ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामिक प्रभाव भी है और इन नियमों के उपाबंध II में उपबर्णित सिद्धान्तों के अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति, के खतरे, घरेलू उद्योग की स्थापना के तात्त्विक गतिरोध और पाटित आयातों और क्षति के बीच कारण संबंध का अवधारण करेगा।

(3) अभिहित प्राधिकारी, असाधारण मामलों में, क्षति की विद्यमानता के बारे में इस बात के होते हुए भी निष्कर्ष दे सकेगा कि घरेलू उद्योग के पर्याप्त भाग को क्षति नहीं हुई है, यदि—

(1) पाटित आयातों का किसी एकल बाजार में संकेन्द्रण है, और

(2) पाटित वस्तुएं ऐसे बाजार के भीतर सभी या लगभग सभी उत्पादन के उत्पादकों को क्षति पहुंचा रही है।

12. प्रारंभिक निष्कर्ष (1) अभिहित प्राधिकारी, अन्वेषण करने के लिए शीघ्रता से कार्यवाही करेगा और समुचित मामलों में, निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य और पाटन-अंतर के बारे में तथा विनिर्दिष्ट देशों से आयातों की बाबत प्रारंभिक निष्कर्ष अभिलिखित करेगा। वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में भी आगे निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और ऐसे निष्कर्ष में, पाटन और क्षति संबंधी प्रारंभिक अवधारणों के लिए पर्याप्त रूप से विस्तृत जानकारी होगी और तथ्य तथा विधि के उन विषयों को, जिनके कारण स्वीकार या अस्वीकार किए जाने के बारे में बहस हुई, निर्दिष्ट किया जाएगा।

इसमें निम्नलिखित भी होगा :—

- (i) प्रदायकताओं के या जब वह साध्य न हो तो, अंतर्बलित प्रदाय करने वाले देशों के नाम।
- (ii) वस्तु का वर्णन, जो सीमाशुल्क प्रयोजनों के लिए पर्याप्त है।
- (iii) स्थायित्व पाटन-अंतर तथा स्थापन में प्रयुक्त वर्गीकरण का पूर्ण स्पष्टीकरण और निर्यात कीमत तथा सामान्य मूल्य का मिलान;
- (iv) क्षति अवधारण से सुसंगत प्रतिफल।
- (v) अवधारण प्रारंभ करने के मुख्य कारण।

(2) अभिहित प्राधिकारी अपने प्रारंभिक निष्कर्षों को अभिलिखित करके एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा।

13. अनंतिम शुल्क का उद्ग्रहण : केन्द्रीय सरकार, अभिहित प्राधिकारी, द्वारा अभिलिखित किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर, पाटन-अंतर से अनधिक अनंतिम शुल्क अधिरोपित कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई शुल्क अभिहित प्राधिकारी द्वारा अन्वेषण आरंभ करने के अपने विनिश्चय की बाबत जारी की गई सार्वजनिक सूचना की तारीख से साठ दिन की समाप्ति से पूर्व अधिरोपित नहीं किया जाएगा; परन्तु यह और कि ऐसा शुल्क छह मास से अधिक अवधि के लिए ही प्रवृत्त रहेगा, जो अंतर्बलित व्यापार की सार्थक प्रतिशतता का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्यातकर्ताओं के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नौ मास तक बढ़ाई जा सकेगी।

14. अन्वेषण की समाप्ति :—अभिहित प्राधिकारी किसी अन्वेषण को समाप्त करने के लिए तुरन्त सार्वजनिक सूचना जारी करेगा, यदि

- (क) वह ऐसे प्रभावित घरेलू उद्योग से या उस की ओर से जिसके अनुरोध पर अन्वेषण आरंभ किया गया था ऐसा करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त करता है, या
- (ख) किसी अन्वेषण के दौरान उसका समाधान हो जाता है कि पाटन का या, जहां लागू हो, क्षति का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जिससे कि अन्वेषण के चालू रखा जाने को न्यायोचित ठहराया जा सके, या

(ग) यह अवधारित करता है कि पाटन का अन्तर आयात कीमत के दो प्रतिशत के कम है, या

(घ) यह अवधारित करता है कि किसी विशिष्ट देश से पाटन आयातों की वास्तविक या संभाव्य मात्रा का लेखा-जोखा वैसे ही उत्पाद के आयातों के तीन प्रतिशत से कम है, तो तब तक, जब तक कि वे देश जो व्यक्तिगत रूप से वैसे ही उत्पाद के आयातों का लेखा-जोखा तीन प्रतिशत से कम देते हैं, सामूहिक रूप से वैसे ही उत्पाद के आयात के आत प्रतिशत से अधिक का लेखा-जोखा देते हैं, या

(ङ) वह अवधारित करता है कि क्षति, जहां लागू हो, नाम मात्र है।

15. अन्वेषण वचनबंध का निलम्बन या समाप्ति :—

(1) अभिहित प्राधिकारी किसी अन्वेषण को निलम्बित या समाप्त कर सकेगा, यदि प्रसंगत वस्तु का निर्यातकर्ता—

(1) अभिहित प्राधिकारी को कीमतों को पुनरीक्षित करने के लिए, लिखित रूप से यह वचनबंध करता है कि उक्त वस्तु का पाटन कीमतों पर भारत में कोई निर्यात नहीं किए जाते हैं, या

(2) विनिर्दिष्ट देशों से आयातों की दशा में कीमतों को पुनरीक्षित करने का वचनबंध करता है ताकि पाटन का हानिकारक प्रभाव दूर किया जा सके और अभिहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि पाटन का हानिकारक प्रभाव दूर कर दिया गया है;

परन्तु ऐसे वचनबंध के परिणामस्वरूप कीमत में कोई वृद्धि इससे अधिक नहीं है जो पाटन-अन्तर को दूर करने के लिए आवश्यक है;

परन्तु यह और कि अभिहित प्राधिकारी यदि निर्यातकर्ता ऐसी बाछ करे या वह ऐसा विनिश्चय करे तो अन्वेषण को पूरा करेगा और अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(2) उपनियम (1) के खंड (ii) के अधीन कीमत वृद्धि से संबंधित कोई वचनबंध किसी निर्यातकर्ता से तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अभिहित प्राधिकारी ने पाटन और क्षति का प्रारंभिक अवधारण नहीं किया हो।

(3) अभिहित प्राधिकारी, किसी निर्यातकर्ता द्वारा प्रति-स्थापित ऐसे वचनबंध भी स्वीकार नहीं कर सकेगा, यदि वह यह समझता है कि ऐसे वचनबंध का स्वीकार किया जाना किसी अन्य कारण से असाध्य या अस्वीकार्य है।

(4) अभिहित प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार को किसी वचनबंध के स्वीकार किए जाने और अन्वेषण के निलम्बन या समाप्ति के बारे में सूचना देगा और इस संबंध में सार्वजनिक सूचना भी जारी करेगा। सार्वजनिक सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ, वचनबंध का अग्रोपनीय भाग होगा।

(5) ऐसे मामलों में जहाँ अभिहित प्राधिकारी द्वारा को वचनबन्ध स्वीकार किया गया है, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 9-क की उपधारा (2) के अधीन उस अवधि के लिए जब अभिहित प्राधिकारी को स्वीकार्य वचनबन्ध विधिमान्य रहता है शुल्क अधिरोपित नहीं कर सकेगी।

(6) जहाँ अभिहित प्राधिकारी ने उपनियम (i) के अधीन कोई वचनबन्ध स्वीकार किया है, वहाँ ऐसे निर्यातकर्ता में, जिससे ऐसा वचनबन्ध स्वीकार किया गया है, समय-समय पर वचनबन्ध के पूरा किए जाने से सुसंगत जानकारी उपलब्ध कराने और सुसंगत आंकड़े का स्थापन अनुज्ञात करने की अपेक्षा कर सकेगा;

परन्तु किसी वचनबन्ध के किसी अतिक्रमण की दशा में, अभिहित प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार को ऐसे अतिक्रमण और अन्वेषण को शीघ्र पूरा करने के बारे में सूचना देगा।

(7) अभिहित प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या प्रश्नगत वस्तु के निर्यातकर्ताओं या आयातकर्ताओं से या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से प्राप्त किसी अनुरोध के आधार पर, पहले दिए गए किसी वचनबन्ध को जारी रखने की आवश्यकता का समय-समय पर पुनर्विचिन्तन करेगा।

16. सूचना का प्रकटीकरण :—अभिहित प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों को देने से पूर्व ऐसे विचाराधीन आवश्यक तथ्यों के बारे में जो उसके विनिश्चय के आधार के भाग रूप हैं; को सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित करेगा।

17. अंतिम निष्कर्ष :—(1) अभिहित प्राधिकारी किसी अन्वेषण के आरंभ किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, यह अवधारित करेगा कि अन्वेषण के अधीन वस्तु भारत में पाटित की जा रही है या नहीं और केन्द्रीय सरकार को :—

(क) निम्नलिखित के बारे में अपने अंतिम निष्कर्ष देगा—

- (i) उक्त वस्तु की निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य और पाटन-अंतर ;
- (ii) विनिर्दिष्ट देशों से आयातों की दशा में, क्या उक्त वस्तु का भारत में आयात किए जाने से, भारत में स्थापित किसी उद्योग को तात्त्विक क्षति होती है या होने की आशंका है या भारत में किसी उद्योग की स्थापना में तात्त्विक रूप से गतिरोध उत्पन्न होता है।
- (iii) जहाँ लागू हो, पाटित आयातों और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध।
- (iv) क्या भूतलक्षी उद्ग्रहण की मांग की जाती है और यदि हां तो, उसके लिए कारण और ऐसे भूतलक्षी उद्ग्रहण के आरंभ की तारीख :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों में, एक वर्ष की पूर्वोक्त अवधि को छह मास तक और बढ़ा सकेगी;

परन्तु यह और कि उन मामलों में, जहाँ अभिहित प्राधिकारी ने नियम 15 में यथा उपबंधित किसी कीमत वचनबन्ध के स्वीकार किए जाने पर अन्वेषण को निलम्बित कर दिया है और तत्पश्चात् वह उसे उक्त वचनबन्ध के निर्वन्धनों का अतिक्रमण होने पर फिर से आरंभ करता है, वहाँ उस अवधि को, जिस तक अन्वेषण को निलम्बनाधीन रखा गया था, एक वर्ष उक्त अवधि का परिनिर्धारित करते समय हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(ख) शुल्क की ऐसी रकम की सिफारिश, जो, यदि उद्ग्रहीत की जाती तो, घरेलू उद्योग को हुई क्षति को जहाँ लागू हो, दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

(2) यदि अंतिम निष्कर्ष सकारात्मक है, तो उसमें तथ्यों और विधि के विषय पर सभी जानकारी और वे कारण, जिनसे निष्कर्ष निकाला गया है, हांगे और इसमें निम्नलिखित के बारे में भी सूचना होगी—

(i) प्रदायकर्ताओं के या जब वह साध्य न हो तो, अंतर्दलित प्रदाय करने वाले देशों के नाम;

(ii) उत्पाद का वर्णन, जो सीमाणानुसंग प्रयोजनों के लिए पर्याप्त है;

(iii) स्थापित पाटन-अंतर और स्थापन में प्रयुक्त वर्गीकरण के लिए कारणों का पूर्ण स्पष्टीकरण तथा निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य का मिलान।

(iv) क्षति असंधारण से सुसंगत प्रतिफल ; और

(v) अवधारण आरंभ करने के मुख्य कारण;

(3) अभिहित प्राधिकारी अन्वेषण के अधीन वस्तु के प्रत्येक ज्ञात निर्यातकर्ता या संबंधित उत्पादक के लिए पाटन अंतर अवधारित करेगा;

परन्तु ऐसे मामलों में जहाँ निर्यातकों, कर्ताओं उत्पादकों, आयातकों अथवा अंतर्दलित वस्तुओं के प्रकार की संख्या इतनी अधिक है कि ऐसे अवधारण को असाध्य बना देते हैं, वहाँ वह अपना निष्कर्ष चयन के समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर विधिमान्य नमूनों का सांख्यिकी रूप से प्रयोग करके हितबद्ध पक्षकारों या वस्तुओं की युक्तियुक्त संख्या तक अथवा प्रश्नगत देश के निर्यात की मात्रा की अधिकतम प्रतिशतता तक, जिसका युक्तियुक्त रूप से अन्वेषण किया जा सकता है, सीमित कर करता है और इस परन्तु के अधीन निर्यातकर्ताओं, उत्पादकों या वस्तुओं के प्रकार का किया गया कोई चयन अधिमानतः; संबंधित निर्यातकर्ताओं, उत्पादकों या आयातकर्ताओं के परामर्श से या उनकी सम्मति से किया जाएगा;

परन्तु यह और कि अभिहित प्राधिकारी किसी निर्यातकर्ता या उत्पादक, भले ही उनका प्रारंभिक रूप से चयन न हुआ हो, जो समय से आवश्यक जानकारी प्रस्तुत कर देता है, सिवाय उस दशा में जहाँ निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों की

संख्या इतनी अधिक है कि पृथक्-पृथक् परीक्षा असम्भव रूप से दुष्वद होगी और अन्वेषण का समय से पूरा होना निर्धारित करेगी, पाटन का पृथक् अंतर अवधारित करेगा।

(4) अभिहित प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष अभिलिखित करने हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा।

18. शुल्क का उद्ग्रहण: (1) केन्द्रीय सरकार, अभिहित प्राधिकारी द्वारा नियम 17 के अधीन अंतिम निष्कर्षों के प्रकाशन से तीन मास के भीतर, अंतिम निष्कर्ष के अन्तर्गत आने वाली वस्तु के भारत में आयात करने पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित कर सकेगी, जो ऐसी कीमत के जिस पर ऐसी वस्तु का भारत को निर्यात किया जाता है और ऐसे सामान्य मूल्य के, जो नियम 17 के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, बीच के अंतर से अधिक नहीं होगा।

परन्तु विनिर्दिष्ट देशों में आयातों की दशा में, शुल्क की रकम उम रकम में, जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त पाई गई है अधिक नहीं होगी।

(2) उन मामलों में, जहां अभिहित प्राधिकारी ने किसी विनिर्दिष्ट देश से निर्यातों की मात्रा की प्रतिशतता, जैसा कि नियम 15 के उपनियम (3) में निर्दिष्ट है, कोई प्रतिपाटन शुल्क, जो परीक्षण में सम्मिलित न किए गए निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों से आयातों को लागू है, चयनित की है, निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा:—

(1) चयनित निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों के संबंध में स्थापित पाटन की भारत औसत अंतर या,

(2) जहां प्रति पाटन शुल्कों के संदाय के लिए दायित्व भावी सामान्य मूल्य के आधार पर परिकलित किया जाता है वहां चयनित निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों के भारत औसत सामान्य मूल्य और पृथक्: परीक्षित न किए गए निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों की निर्यात कीमतों के बीच अंतर:

परन्तु केन्द्रीय सरकार इस उपनियम के प्रयोजन के लिए किसी शून्य अंतर को, ऐसे अंतर जो, दो प्रतिशत से कम हैं, और जिन्हें प्रतिशतता या निर्यात कीमत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, और वे अंतर जो नियम 6 के उपनियम (8) में दी गई परिस्थितियों में स्थापित किए गए हैं, हिसाब में नहीं लेगी। केन्द्रीय सरकार परीक्षण में सम्मिलित न किए गए उस किसी निर्यातकर्ता या उत्पादक से निर्यात को पृथक् शुल्क लागू करेगी, जिसने नियम 15 के उपनियम (3) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट अन्वेषण के दौरान आवश्यक जानकारी दी है।

(3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी घरेलू उद्योग का नियम 2 के खंड (ख) के परन्तुक के अनुसार निर्वातन किया गया है, वहां निर्यातकर्ताओं को शुल्क संबंध क्षेत्र को पाटन कीमतों पर निर्यात समाप्त

करने का अवसर देने के पश्चात् ही उद्ग्रहीत किया जाएगा या अन्यथा नियम 15 के अनुसरण में वचनबंध देता है और ऐसा वचनबंध शीघ्रता से नहीं दिया गया है, और ऐसे मामलों में शुल्क केवल उन विनिर्दिष्ट उत्पादकों की वस्तुओं पर उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा, जो प्रसन्न क्षेत्र में प्रदाय करते हैं।

(4) यदि अभिहित प्राधिकारी का अंतिम निष्कर्ष नकारात्मक है, वह ऐसे प्रथम दृष्टया साक्ष्य के प्रतिकूल है, जिसके आधार पर अन्वेषण प्रारंभ किया गया था, तो केन्द्रीय सरकार, अभिहित प्राधिकारी द्वारा नियम 17 के अधीन अंतिम निष्कर्षों के प्रकाशन के पैंतालीस दिन के भीतर अधिरोपित अंतिम शुल्क यदि कोई हो, वापस ले लेगी।

19. अविषेदकारी आधार पर शुल्क का अधिरोपण:— नियम 13 के अधीन अधिरोपित कोई अंतिम शुल्क या नियम 18 के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क अविषेदकारी आधार पर होगा और ऐसी वस्तुओं के सभी आयातों को, चाहे वे किन्हीं भी स्रोतों से पाटित पाई जाएं और जहां लागू हो, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को, सिवाय उन स्रोतों से आयातों की दशा में, जिनसे नियम 15 के निबंधनों के अनुसार वचनबंध स्वीकार किया गया है, लागू होगा।

20. शुल्क का प्रारम्भ: (1) नियम 13 और नियम 18 के अधीन उद्ग्रहणीय प्रति पाटन शुल्क राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) जहां कोई अंतिम शुल्क उद्ग्रहीत किया गया है और जहां अभिहित प्राधिकारी ने क्षति का निष्कर्ष अभिलिखित किया है या जहां अभिहित प्राधिकारी ने क्षति की प्राप्ति का निष्कर्ष अभिलिखित किया है और यद्यपि यह निष्कर्ष है कि अंतिम शुल्क के अभाव में पाटित आयातों के प्रभाव के कारण क्षति होगी, वहां प्रतिपाटन शुल्क अंतिम शुल्क के अधिरोपण की तारीख से उद्ग्रहीत किया जा सकेगा।

(ख) अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (3) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, प्रतिपाटन शुल्क ऐसे अंतिम शुल्क के अधिरोपण के पूर्व नब्बे दिन के प्रारम्भ की तारीख से भूतलक्षी रूप से उद्ग्रहीत किया जा सकेगा;

परन्तु कोई शुल्क अन्वेषण के प्रारम्भ से पहले देशी उपभोग के लिए किए गए आयातों पर भूतलक्षी रूप से उद्ग्रहीत नहीं होगा।

परन्तु यह और कि नियम 15 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट कीमत वचनबंध के प्रतिक्रमण के मामलों में, कोई शुल्क ऐसे आयातों पर, जो वचनबंध के निबंधनों के अति-

क्रमण से पहले देशी उपभोग के लिए किए गए हैं, भूतलक्षी रूप से उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

21. शुल्क का प्रतिदाय :—(1) यदि अभिहित प्राधिकारी द्वारा किए गए अन्वेषण के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क पहले ही अधिरोपित और संगृहीत अनंतिम शुल्क से अधिक है, तो अन्तर का आयातकर्ता से संग्रहण नहीं किया जाएगा।

(2) यदि अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् नियत प्रतिपाटन शुल्क पहले ही अधिरोपित और संगृहीत अनंतिम शुल्क से कम है, तो अन्तर को आयातकर्ता को वापस कर दिया जाएगा।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत 19 के उप-नियम 243 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित अनंतिम शुल्क वापस ले लिया गया है, तो पहले ही अधिरोपित और संगृहीत अनंतिम शुल्क, यदि कोई हो, आयातकर्ता को वापस कर दिया जाएगा।

22. भूलतः अन्वेषण न किए गए निर्यातकर्ताओं के लिए पाटन अनंतिम—(1) यदि कोई उत्पाद प्रति पाटन के अधीन है तो अभिहित प्राधिकारी प्रसंगत निर्यात करने वाले देश में किन्हीं निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों के लिए जिन्होंने अन्वेषण की अवधि के दौरान भारत को उत्पाद, का निर्यात नहीं किया है, पाटन के पृथक् अंतर के अवधारण के प्रयोजन के लिए कालिक पुनर्विलोकन करेगा परन्तु यह तब कि जब निर्यातकर्ता या उत्पादक निर्यात करने वाले देश में किसी ऐसे निर्यातकर्ता या उत्पादक से संबंधित नहीं हैं जो उत्पाद पर प्रति पाटन शुल्क के अधीन हैं।

(2) केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन की अवधि के दौरान ऐसे निर्यातकर्ताओं के या उत्पादकों से आयात पर प्रति पाटन शुल्क उपगृहीत नहीं करेगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार अनंतिम निर्धारण कर सकती है और आयातकर्ता से गारंटी ले सकती है, यदि अभिहित प्राधिकारी ऐसी सिफारिश करता है और यदि ऐसे पुनर्विलोकन का परिणाम ऐसे उत्पादों या निर्यातकर्ताओं की बाबत पाटन का अवधारण करना होता है तो वह ऐसे मामलों में पुनर्विलोकन के प्रारम्भ की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क उद्गृहीत कर सकती है।

23. पुनर्विलोकन :—(1) अभिहित प्राधिकारी, समय-समय पर, प्रतिपाटन शुल्क के निरन्तर अधिरोपण की आवश्यकता का पुनर्विलोकन करेगा और यदि उसका उसके द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे शुल्क निरन्तर अधिरोपण के लिए कोई न्यायोचित्य नहीं है तो वह केन्द्रीय सरकार को उसके वापस लिए जाने की सिफारिश करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रारम्भ किया कोई पुनर्विलोकन ऐसे पुनर्विलोकन के प्रारम्भ की तारीख से बारह मास से अनधिक अवधि के भीतर समाप्त किया जाएगा।

(3) नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध पुनर्विलोकन के मामले में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

24. किसी तीसरे देश को पाटन में क्षति कारित करना :—(1) अभिहित प्राधिकारी भारत में होने वाले अभिकथित किसी पाटन करने में और किसी ऐसे तीसरे देश के, जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने में अन्वेषण प्रारम्भ कर सकेगा।

(2) अभिहित प्राधिकारी टैरिफ और व्यापार के बारे में साधारण करार, 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार के सम्बन्ध में उल्लेख्य दौर के बहुउद्देशीय व्यापार समझौता के अंतिम अधिनियम में अभिकथित प्रक्रियों का अनुसरण करेगा।

उपाबंध

प्रसामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन अंतर के अवधारण को शासित करने वाले सिद्धान्त

अभिहित प्राधिकारी प्रसामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन अंतर का अवधारण करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धान्तों को विचार में लेगा :—

1. प्रसामान्य मूल्य के अवधारण के संदर्भ में निर्दिष्ट लागत-तत्वों का सामान रूप से अवधारण, अन्वेषणाधीन निर्यातकर्ता या उत्पादक द्वारा रखे गए अभिलेख के आधार पर किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि ऐसे अभिलेख निर्यातकर्ता देश के सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार हों और ऐसे अभिलेखों से विचाराधीन वस्तु के उत्पादन और विक्रय से संबंध लागत युक्तियुक्त रूप से प्रतिबंधित होता हो।

2. (i) निर्यातकर्ता देश के घरेलू बाजार में वैसी ही उत्पाद के विक्रय या किसी तीसरे देश को, प्रशासनिक विक्रय और साधारण लागत सहित प्रति यूनिट उत्पादन लागत से कम कीमत पर (नियत और परिवर्ती) किए गए विक्रयों को ऐसे विक्रय माना जा सकेगा जो कीमत के कारण व्यापार के सामान्य अनुक्रम में नहीं आते हैं। अभिहित प्राधिकारी, प्रसामान्य मूल्य का अवधारण करते समय, इन विक्रयों को हिसाब में नहीं ले सकता है परन्तु यह सब जब कि उसने यह अवधारित किया हो कि—

(i) ऐसे विक्रय युक्तियुक्त कालावधि के भीतर (छह मास से अन्यून) पर्याप्त मात्राओं में किए जाते हैं, अर्थात् जब वस्तु की भारत औसत विक्रय कीमत प्रति यूनिट भारत औसत लागत से कम

हैं या जब प्रति यूनिट लागत से कम कीमत पर किए गए विक्रयों की मात्रा विचाराधीन संव्यवहारों में विक्रय की गई मात्रा के 20 प्रतिशत से कम नहीं है; और

- (ii) ऐसे विक्रय ऐसी कीमतों पर किए गए हैं जिनकी युक्तियुक्त कालावधि के भीतर, सभी लागतों की वसूली की व्यवस्था नहीं की गई है। उक्त कीमतों के बारे में युक्तियुक्त कालावधि के भीतर लागतों की वसूली की व्यवस्था करना तब माना जाएगा यदि वे अन्वेषण की अवधि के लिए प्रति यूनिट भारित औसत लागत से ऊपर हैं भले ही वे विक्रय के समय प्रति यूनिट लागत से कम रही हों।

3. (i) उक्त प्राधिकारी, अन्वेषण के दौरान, लागत के समुचित आबंटन से संबंधित सभी उपलब्ध साक्ष्य पर, जिसके अन्तर्गत वह साक्ष्य भी है जो निर्यातकर्ता या उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, विचार करेगा, परन्तु यह तब जब कि ऐसे आबंटन का निर्यातकर्ता या उत्पादक द्वारा पूंजी व्यय और अन्य विकास लागतों का क्रमिक अपाकरण स्थापित करने और अवक्षयण अवधि और मॉके के संबंध में ऐतिहासिक रीति में उपयोग किया गया हो।

(ii) जब तक कि ऊपर खंड (1) और उपखंड (i) में निर्दिष्ट लागत आबंटन में पहले से प्रतिबिम्बित न किया गया हो, अभिहित प्राधिकारी लागत के उन अनावर्ती मदों के लिए, जो अतिरिक्त और/या चालू उत्पादन के लिए फायदाप्रव है या ऐसी परिस्थितियों के लिए, जिनमें अन्वेषण की अवधि के दौरान लागत पर प्रचालन के आरम्भ द्वारा प्रभाव पड़ता है, समुचित समाधान भी करेगा।

4. अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट प्रशासनिक विक्रय और साधारण लागत तथा लाभों के लिए रकमों, अन्वेषणाधीन निर्यातकर्ता या उत्पादक द्वारा जैसे ही उत्पाद के, व्यापार के सामान्य अनुक्रम में किए गए, उत्पादन और विक्रयों से संबंधित वास्तविक डाटा पर आधारित होंगी। जब ऐसी रकमों का अवधारण इस आधार पर नहीं किया जा सके तब रकमों निम्नलिखित आधार पर अवधारित की जा सकेंगी :—

- (i) प्रश्नगत निर्यातकर्ता या उत्पादक द्वारा उद्भव के देश के घरेलू बाजार में उसी साधारण प्रवर्ग की वस्तु के उत्पादन और विक्रय की द्वाारा उपगत और वसूल की गई वास्तविक रकमों ;
- (ii) अन्वेषण के अध्ययाधीन अन्य निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों द्वारा उद्भव के देश के घरेलू बाजार में वैसी ही वस्तु के उत्पादन और विक्रय की बाबत उपगत और वसूल की गई वास्तविक रकमों की भारित औसत।
- (iii) कोई अन्य युक्तियुक्त पद्धति, परन्तु यह तब जब कि इस प्रकार स्थापित लाभ के लिए रकम

निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों द्वारा उद्भव के देश में घरेलू बाजार में उसी साधारण प्रवर्ग के उत्पादों के विक्रय पर सामान्य रूप से प्राप्त लाभ से अधिक नहीं होगी।

5. अभिहित प्राधिकारी प्रलक्षित निर्यात कीमत निकालते समय लागत के लिए जिसके अन्तर्गत ऐसे शुल्क और कर भी हैं जो आयात और पुनर्विक्रय के बीच उपगत किए जाते हैं और लाभों के लिए आवश्यक मोक प्रदान करेगा।

6. (i) अभिहित प्राधिकारी पाटन अंतर निकालते समय निर्यात कीमत और प्रसामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा। तुलना व्यापार के उसी स्तर पर सामान्यतः कारखाना द्वार स्तर पर और यथासंभव निकटतम रूप से उसी समय किए गए विक्रयों की बाबत की जाएगी। प्रत्येक मामले में उसके गुणगुण के आधार पर ऐसे अंतरों के लिए जो कीमत-तुल्यता को प्रभावित करते हैं जिनके अंतर्गत विक्रय की शर्तों और निबंधनों, कराधान व्यापार के स्तरों, मात्राओं, भौतिक लक्षणों में अंतर और ऐसे कोई अन्य अंतर भी हैं, जो कीमत-तुल्यता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं सम्यक मोक दी जाएगी।

(ii) ऐसे मामलों में जिनमें निर्यात कीमत प्रलक्षित कीमत है व्यापार के समतुल्य स्तर पर सामान्य मूल्य स्थापित करने के पश्चात् ही तुलना की जाएगी।

(iii) जब इस पैरा के अधीन तुलना करने से मुद्दाओं के संपरिवर्तन की अपेक्षा हो तब ऐसी संपरिवर्तन विक्रय की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके किया जाना चाहिए परन्तु जब बायदा बाजार में विक्रय या विदेशी मुद्रा का प्रत्यक्ष संबंध अंतर्बलित निर्यात विक्रय से हो तब बायदा विक्रय में की विनिमय दर का उपयोग किया जाएगा। विनिमय दरों में उतार-चढ़ावों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और किसी अन्वेषण में निर्यातकर्ताओं की अन्वेषण की अवधि के दौरान विनिमय दरों में अचिरत संचालन दर्शाने के लिए अपनी निर्यात कीमतों को समायोजित करने के लिए कम से कम 60 दिन का समय दिया जाएगा।

(iv) इस पैरा में तुलना को शासित करने वाले उपबंध के अधीन रहते हुए अन्वेषण काल के दौरान पाटन अंतर की विद्यमानता सामान्यतया प्रत्येक संव्यवहार पर भारित औसत प्रसामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों की तुलना के आधार पर स्थापित की जाएगी। भारित औसत आधार पर स्थापित सामान्य मूल्य की अलग-अलग निर्यात संव्यवहार की कीमत से तुलना की जा सकेंगी यदि यह पाया जाता है कि निर्यात कीमतों की कोई पद्धति भिन्न-भिन्न क्षेत्रों या कालावधियों के मध्य महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है और यदि इस बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया जाता है कि ऐसे अंतरों को एक भारित औसत से दूसरी भारित औसत या एक संव्यवहार की दूसरे संव्यवहार से तुलना करके समुचित रूप से हिमाज में क्यों नहीं लिया जा सकता।

उपाबंध-2

क्षति का अवधारण करने के लिए सिद्धांत

अभिहित प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति या तात्विक क्षति के खतरे या ऐसे उद्योग स्थापित करने में तात्विक गतिरोध जिसे इसमें इसके पश्चात् "क्षति" का गया है और पाटित आयात और ऐसी क्षति के बीच आक्रामिक संबंध का अवधारण करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धान्तों को विचार में रखेगा—

(i) क्षति के अवधारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में वैसी ही वस्तु की कीमतों पर पाटित आयात के प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के पारिणामिक प्रभाव दोनों की वस्तुपरक परीक्षा अंतर्बलित होगी।

(ii) पाटित आयातों की मात्रा की परीक्षा करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या पाटित आयात में आयाधिक रूप से या भारत में उत्पादन या उपयोग के सापेक्ष महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। नियम 18 के उप-नियम (2) में यथानिर्दिष्ट कीमतों पर पाटित आयात के प्रभाव के संबंध में अभिहित प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या भारत में वैसी ही उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमत में महत्वपूर्ण रूप से कमी हुई है या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण मात्रा अन्यथा घटाना या कीमत में ऐसी वृद्धि को अन्यथा हुई होती महत्वपूर्ण मात्रा तक रोकना है।

(iii) ऐसे मामलों में जिनमें किसी उत्पाद के एक से अधिक देश से किए गए आयातों का साथ-साथ पाटन अन्वेषण किया जा रहा हो अभिहित प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से निर्धारण केवल तब करेगा जब कि वह यह अवधारित करता है कि (क) प्रत्येक देश से किए गए आयातों के संबंध में स्थापित पाटन अंतर की प्रतिशतता निर्यात कीमत की अभिव्यक्त प्रतिशतता के दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से किए गए आयातों की मात्रा वैसी ही वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत है या जहां किसी एक देश का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है वहां सामूहिक रूप से आयात वैसी ही वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक है और (ख) आयातित वस्तु और वैसी ही देशी वस्तुओं के बीच प्रतियोगिता की शर्तों को ध्यान में रखते हुए आयात के प्रभाव का संचयी निर्धारण समुचित है।

(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की परीक्षा के अंतर्गत उन सभी सुसंगत आर्थिक कारकों और सूचकों का मूल्यांकन आएगा जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जिसके अंतर्गत विक्रय लाभ उत्पादन बाजार शेयर उत्पादकता निवेश परलाभ या क्षमता की उपयोगिता में आकृतिक और संभाव्य गिरावट देशी कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक पाटन अंतर का परिमाण नकद प्रवाह

सामान सूचियों नियोजन मजदूरी, मजदूरी, उत्पादन पूंजी-निवेश लेने की योग्यता पर वास्तविक और संभाव्य नकारात्मक प्रभाव भी है।

(v) यह अवश्य ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि पाटित आयात उपरोक्त पैरा (ii) और पैरा (iv) में यथा उपवर्णित पाटन के ऐसे प्रभावों से किए गए हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति पारित करते हैं। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच आक्रामिक संबंध का प्रदर्शन अभिहित प्राधिकारी के समक्ष सुसंगत साक्ष्य की परीक्षा पर आधारित होगा। अभिहित प्राधिकारी पाटित आयात से भिन्न किन्हीं ऐसे ज्ञात कारकों की भी परीक्षा करेगा जो उसके साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं और इन अन्य कारकों द्वारा हुई क्षति पाटित आयातों के फलस्वरूप हुई नहीं मानी जानी चाहिए। उन कारकों के अंतर्गत जो इस संबंध में सुसंगत हो सकते हैं अन्य बातों के साथ-साथ पाटन कीमतों पर विक्रय न किए गए आयातों की मात्रा और कीमतें मांग में संकुचन या उपभोग की पद्धतियों में परिवर्तन विदेशी और देशी उत्पादकों के अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और उनके बीच प्रतियोगिता प्रौद्योगिकी और निर्यात संपादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता में विकास भी हैं।

(vi) पाटित आयातों के प्रभाव का निर्धारण वैसी ही वस्तु के घरेलू उत्पादन के संबंध में किया तब जाएगा जब उपलब्ध आंकड़ों से ऐसी कसौटियों जैसे उत्पादन प्रक्रिया उत्पादकों के विक्रय और लाभ के आधार पर उस उत्पादन की पृथक पहचान की जा सकती है। यदि उस उत्पादन की ऐसी पृथक पहचान संभव नहीं है तो पाटित आयातों के प्रभाव का निर्धारण ऐसे उत्पादों के जिनके अंतर्गत वैसी ही उत्पाद भी हैं जिनके लिए आवश्यक जानकारी दी जा सकती है निकटतम समूह या रैंज के उत्पादन की परीक्षा करके किया जाएगा।

(vii) तात्विक क्षति के खतरे का अवधारण तथ्यों पर न कि मात्र अभिकथन कल्पना या दूरस्थ संभाव्यता पर आधारित होगा। परिस्थितियों के ऐसे परिवर्तन की जिससे पाटन से क्षति कारित होने की स्थिति उत्पन्न होगी स्पष्टतः पूर्वकल्पना की जानी चाहिए और वह परिवर्तन आसन्न होना चाहिए। तात्विक क्षति के किसी खतरे की विद्यमानता के संबंध में अवधारण करते समय अभिहित प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ इन कारकों पर विचार करेगा जैसे:

(क) भारत में पाटित आयातों की दर में ऐसी महत्वपूर्ण वृद्धि जिससे पर्याप्त रूप से बड़े हुए आयात की संभावना उपदर्शित होती हो;

(ख) निर्यातकर्ता की पर्याप्ततः निर्बाध रूप से क्षमता या इसकी क्षमता में आसन्न व्यय योग्य सारवान वृद्धि जिससे किन्हीं अतिरिक्त निर्यातों को आमेलित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को हिसाब में लेते हुए भारतीय बाजार में बड़े हुए पाटित निर्यातों की संभाव्यता उपदर्शित होती हो;

- (ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर किए जा रहे हैं जिनका प्रभाव देशी कीमतों का महत्वपूर्ण रूप से कम करना या दबाना होगा और जिससे और अधिक आयातों की मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी, और
- (घ) ऐसे उत्पाद की सूचियां जिनका अन्वेषण किया जा रहा है।

[फा सं. 525/2/94 सी. शु. (टी. यू.)]

एस. एम. भटनागर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

No. 2/95-N.T.—CUSTOMS

New Delhi, the 1st January, 1995

G.S.R. 1(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 9A and sub-section (2) of section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in supersession of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1985, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the 1st day of January, 1995.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975),
- (b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry :

Provided that in exceptional circumstances referred to in sub-rule (3) of rule 11, the domestic industry in relation to the article in question shall be deemed to comprise two or more competitive markets and the producers within each of such market a separate industry, if—

- (i) the producers within such a market sell all or almost all of their production of the article in question in that market, and
- (ii) the demand in the market is not in any substantial degree supplied by producers of the said article located elsewhere in the territory ;
- (c) "Interested party" includes—
- (i) an exporter or a foreign producer or the importer of an article subject to investigation for being dumped in India, or a trade or business association a majority of the members of which are producers, exporters or importers of such an article ;

(ii) the government of the exporting country ; and

(iii) a producer of the like article in India or a trade and business association a majority of the members of which produce the like article in India ;

(d) "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such an article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation ;

(e) "provisional duty" means an anti-dumping duty imposed under sub-section (2) of section 9A of the Act ;

(f) "specified country" means a country or territory which is a member of the World Trade Organisation and includes the country or territory with which the Government of India has an agreement for giving it the most favoured nation treatment ;

(g) all words and expressions used and not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Appointment of designated authority.—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a person not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India or such other person as that Government may think fit as the designated authority for purposes of these rules.

(2) The Central Government may provide to the designated authority the services of such other persons and such other facilities as it deems fit.

4. Duties of the designated authority.—(1) It shall be the duty of the designated authority in accordance with these rules—

- (a) to investigate as to the existence, degree and effect of any alleged dumping in relation to import of any article ;
- (b) to identify the article liable for anti-dumping duty ;
- (c) to submit its findings, provisional or otherwise to Central Government as to—
- (i) normal value, export price and the margin of dumping in relation to the article under investigation ; and
- (ii) the injury or threat of injury to an industry established in India or material retardation to the establishment of an industry in India consequent upon the import of such article from the specified countries.
- (d) to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry and the date of commencement of such duty ; and
- (e) to review the need for continuance of anti-dumping duty.

5. Initiation of investigation.—(1) Except as provided in sub-rule (4), the designated authority shall initiate an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping only upon receipt of a written application by or on behalf of the domestic industry.

(2) An application under sub-rule (1) shall be in the form as may be specified by the designated authority and the application shall be supported by evidence of—

- (a) dumping,
- (b) injury, where applicable, and
- (c) where applicable, a causal link between such dumped imports and alleged injury.

(3) The designated authority shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1) unless—

- (a) it determines, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the appli-

cation expressed by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry:

Provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than twenty five per cent of the total production of the like article by the domestic industry, and

(b) it examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding—

- (i) dumping,
 - (ii) injury, where applicable, and
 - (iii) where applicable, a causal link between such dumped imports and the alleged injury,
- to justify the initiation of an investigation.

Explanation.—For the purpose of this rule the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty per cent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition, as the case may be, to the application.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the designated authority may initiate an investigation suo motu if it is satisfied from the information received from the Collector of Customs appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or from any other source that sufficient evidence exists as to the existence of the circumstances referred to in clause (b) of sub-rule (3).

(5) The designated authority shall notify the government of the exporting country before proceeding to initiate an investigation.

6. Principles governing investigations.—(1) The designated authority shall, after it has decided to initiate investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of any article, issue a public notice notifying its decision and such public notice shall, inter alia, contain adequate information on the following:—

- (i) the name of the exporting country or countries and the article involved;
- (ii) the date of initiation of the investigation;
- (iii) the basis on which dumping is alleged in the application;
- (iv) a summary of the factors on which the allegation of injury is based;
- (v) the address to which representations by interested parties should be directed; and
- (vi) the time-limits allowed to interested parties for making their views known.

(2) A copy of the public notice shall be forwarded by the designated authority to the known exporters of the article alleged to have been dumped, the governments of the exporting countries concerned and other interested parties.

(3) The designated authority shall also provide a copy of the application referred to in sub-rule (1) of rule 5 to—

- (i) the known exporters or to the concerned trade association where the number of exporters is large, and
- (ii) the governments of the exporting countries:

Provided that the designated authority shall also make available a copy of the application to any other interested party who makes a request therefor in writing.

(4) The designated authority may issue a notice calling for any information, in such form as may be specified by it, from the exporters, foreign producers and other interested parties and such information shall be furnished by such persons in writing within thirty days from the date of receipt of the notice or within such extended period as the designated authority may allow on sufficient cause being shown.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the designated authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country.

(5) The designated authority shall also provide opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organisations in cases where the article is commonly sold at the retail level, to furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping injury where applicable, and casualty.

(6) The designated authority may allow an interested party or its representative to present the information relevant to the investigation orally but such oral information shall be taken into consideration by the designated authority only when it is subsequently reproduced in writing.

(7) The designated authority shall make available the evidence presented to it by one interested party to the other interested parties, participating in the investigation.

(8) In a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the designated authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances.

7. Confidential informations.—(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

8. Accuracy of the information.—Except in cases referred to in sub-rule (8) of rule 6, the designated authority shall during the course of investigation satisfy itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties upon which its findings are based.

9. Investigation in the territory of other specified countries.—The designated authority may carry out investigation in the territories of other countries, if the circumstances of a case so warrant:

Provided that the designated authority obtains the consent of the person concerned and notifies the representatives of the concerned government and the concerned government does not object to such investigation.

10. Determination of normal value, export price and margin of dumping.—An article shall be considered as being dumped if it is exported from a country or territory to India at a price less than its normal value and in such circumstances the designated authority shall determine the normal value, export prices and the margin of dumping taking into account, inter-alia, the principles laid down in Annexure I to these rules.

11. Determination of injury.—(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry in India.

(2) The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure-II to these rules.

(3) The designated authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury even where a substantial portion of the domestic industry is not injured, if—

- (i) there is a concentration of dumped imports into an isolated market, and
- (ii) the dumped articles are causing injury to the producers of all or almost all of the production within such market.

12. Preliminary findings.—(1) The designated authority shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and shall, in appropriate cases, record a preliminary finding regarding export price, normal value and margin of dumping, and in respect of imports from specified countries, it shall also record a further finding regarding injury to the domestic industry and such finding shall contain sufficiently detailed information for the preliminary determinations on dumping and injury and shall refer to the matters of fact and law which have led to arguments being accepted or rejected. It will also contain—

- (i) the names of the suppliers, or when this is impracticable, the supplying countries involved;
- (ii) a description of the article which is sufficient for customs purposes;
- (iii) the margins of dumping established and a full explanation of the reasons for the methodology used in the establishment and comparison of the export price and the normal value;
- (iv) considerations relevant to the injury determination; and
- (v) the main reasons leading to the determination.

(2) The designated authority shall issue a public notice recording its preliminary findings.

13. Levy of provisional duty.—The Central Government may, on the basis of the preliminary findings recorded by the designated authority, impose a provisional duty not exceeding the margin of dumping:

Provided that no such duty shall be imposed before the expiry of sixty days from the date of the public notice issued by the designated authority regarding its decision to initiate investigations:

Provided further that such duty shall remain in force only for a period not exceeding six months which may upon request of the exporters representing a significant percentage of the trade involved be extended by the Central Government to nine months.

14. Termination of investigation.—The designated authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if—

- (a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated;
- (b) it is satisfied in the course of an investigation, that there is not sufficient evidence of dumping or, where applicable, injury to justify the continuation of the investigation;

(c) it determines that the margin of dumping is less than two per cent of the export price;

(d) it determines that the volume of the dumped imports, actual or potential, from a particular country accounts for less than three per cent of the imports of the like product, unless, the countries which individually account for less than three per cent of the imports of the like product, collectively account for more than seven per cent of the import of the like product; or

(e) it determines that the injury where applicable, is negligible.

15. Suspension or termination of investigation on price undertaking.—(1) The designated authority may suspend or terminate an investigation if the exporter of the article in question,—

- (i) furnishes an undertaking in writing to the designated authority to revise the prices so that no exports of the said article are made to India at dumped prices; or
- (ii) in the case of imports from specified countries undertake to revise the prices so that injurious effect of dumping is eliminated and the designated authority is satisfied that the injurious effect of the dumping is eliminated;

Provided further that the designated authority shall complete the investigation and record its finding, if the exporter so desires, or it so decides.

(2) No undertaking as regards price increase under clause (i) of the sub-rule (1) shall be accepted from any exporter unless the designated authority had made preliminary determination of dumping and the injury.

(3) The designated authority may, also not accept undertakings offered by any exporter, if it considers that acceptance of such undertaking is impractical or is unacceptable for any other reason.

(4) The designated authority shall intimate the acceptance of an undertaking and suspension or termination of investigation to the Central Government and also issue a public notice in this regard. The public notice shall, contain inter-alia, the non-confidential part of the undertaking.

(5) In cases where an undertaking has been accepted by the designated authority the Central Government may not impose a duty under sub-section (2) of section 9A of the Act for such period the undertaking acceptable to the designated authority remains valid.

(6) Where the designated authority has accepted any undertaking under sub-rule (1), it may require the exporter from whom such undertaking has been accepted to provide from time to time information relevant to the fulfilment of the undertaking and to permit verification of relevant data:

Provided that in case of any violation of an undertaking, the designated authority shall intimate to the Central Government regarding such violation and complete the investigation expeditiously.

(7) The designated authority shall, suo motu or on the basis of any request received from exporters or importers of the article in question or any other interested party, review from time to time the need for the continuation of any undertaking given earlier.

16. Disclosure of information.—The designated authority shall, before giving its final findings, inform all interested parties of the essential facts under consideration which form the basis for its decision.

17. Final findings.—(1) The designated authority shall, within one year from the date of initiation of an investigation, determine as to whether or not the article under investigation is being dumped in India and submit to the Central Government its final finding—

(a) as to,—

- (i) the export price normal value and the margin of dumping of the said article;

- (ii) whether import of the said article into India, in the case of imports from specified countries, causes or threatens material injury to any industry established in India, or materially retards the establishment of any industry in India;
- (iii) a causal link, where applicable, between the dumped imports and injury;
- (iv) whether a retrospective levy is called for and if so, the reasons therefor and date of commencement of such retrospective levy;

Provided that the Central Government may, in circumstances of exceptional nature, extend further the aforesaid period of one year by six months;

Provided further that in those cases where the designated authority has suspended the investigation on the acceptance of a price undertaking as provided in rule 15 and subsequently resumes the same on violation of the terms of the said undertaking, the period for which investigation was kept under suspension shall not be taken into account while calculating the period of said one year.

(b) recommending the amount of duty which, if levied, would be adequate to remove the injury where applicable, to the domestic industry.

(2) The final finding if affirmative, shall contain all information on the matter of facts and law and reasons which have led to the conclusion and shall also contain information regarding—

- (i) the names of the suppliers, or when this is impracticable, the supplying countries involved;
- (ii) a description of the product which is sufficient for customs purposes;
- (iii) the margins of dumping established and a full explanation of the reasons for the methodology used in the establishment and comparison of the export price and the normal value;
- (iv) considerations relevant to the injury determination; and
- (v) the main reasons leading to the determination.

(3) The designated authority shall determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the article under investigation.

Provided that in cases where the number of exporters, producers, importers or types of articles involved are so large as to make such determination impracticable, it may limit its findings either to a reasonable number of interested parties or articles by using statistically valid samples based on information available at the time of selection, or to the largest percentage of the value of the exports from the country in question which can reasonably be investigated, and any selection of exporters, producers or types of articles, made under this proviso shall preferably be made in consultation with and with the consent of the exporters, producers or importers concerned.

Provided further that the designated authority shall, determine an individual margin of dumping for any exporter or producer, though not selected initially, who submit necessary information in time, except where the number of exporters or producers are so large that individual examination would be unduly burdensome and prevent the timely completion of the investigation.

(4) The designated authority shall issue a public notice recording its final findings.

18. Levy of duty.—(1) The Central Government may, within three months of the date of publication of final findings by the designated authority under rule 17, impose by notification in the Official Gazette, upon importation into India of the article covered by the final finding, anti-dumping duty not exceeding the margin of dumping as determined under rule (17).

Provided that in case of imports from the specified countries the amount of duty shall not exceed the amount which has been found adequate to remove the injury to domestic industry.

(2) In cases where the designated authority has selected percentage of the volume of the exports from a particular country, as referred to sub-rule (3) of rule 17, any dumping duty applied to imports from exporters or producers not included in the examination shall not exceed—

- (i) the weighted average margin of dumping established with respect to the selected exporters or producers or,
- (ii) where the liability for payment of anti-dumping duties is calculated on the basis of a prospective normal value, the difference between the weighted average normal value of the selected exporters or producers and the export prices of exporters or producers, not individually examined;

Provided that the Central Government shall disregard for the purpose of this sub-rule any zero margin, margins which are less than 2 per cent expressed as the percentage of export price and margins established in the circumstances detailed in sub-rule (8) of rule 6. The Central Government shall apply individual duties to imports from any exporter or producer not included in the examination who has provided the necessary information during the course of the investigation as referred to in the second proviso to sub-rule (3) of rule 17.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where a domestic industry has been interpreted according to the proviso to sub-clause (b) of rule 2, a duty shall be levied only after the exporters have been given opportunity to cease exporting at dumped prices to the area concerned or otherwise give an undertaking pursuant to rule 15 and such undertaking has not been promptly given and in such cases duty shall not be levied only on the articles of specific producers which supply the area in question.

(4) If the final finding of the designated authority is negative that is contrary to the evidence on whose basis the investigation was initiated, the Central Government shall, within forty five days of the publication of final findings by the designated authority under rule 17, withdraw the provisional duty imposed, if any.

19. Imposition of duty on non discriminatory basis.—Any provisional duty imposed under rule 13 or an anti-dumping duty imposed under rule 18 shall be on a non-discriminatory basis and applicable to all imports of such articles, from whatever sources found dumped and, where applicable, causing injury to domestic industry except in the case of imports from those sources from which undertaking in terms of rule 15 has been accepted.

20. Commencement of duty :—(1) The anti-dumping duty levied under rule 13 and rule 19 shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) :—

- (a) where a provisional duty has been levied and where the designated authority has recorded a final finding of injury or where the designated authority has recorded a final finding of threat of injury and a further finding that the effect of dumped imports in the absence of provisional duty would have led to injury, the anti dumping duty may be levied from the date of imposition of provisional duty ;

- (b) in the circumstances referred to in sub-section (3) of section 9-A of the Act, the anti-dumping duty may be levied retrospectively from the date commencing ninety days prior to the imposition of such provisional duty ;

Provided that no duty shall be levied retrospectively on imports entered for home consumption before initiation of the investigation :

Provided further that in the cases of violation of price undertaking referred to in sub-rule (6) of rule 15, no duty shall be levied retrospectively on the imports which have entered for home consumption before the violation of the terms of such undertaking.

21. Refund of duty :—(1) If the anti-dumping duty imposed by the Central Government on the basis of the final findings of the investigation conducted by the designated authority is higher than the provisional duty already imposed and collected, the differential shall not be collected from the importer.

(2) If, the anti dumping duty fixed after the conclusion of the investigation is lower than the provisional duty already imposed and collected, the differential shall be refunded to the importer.

(3) If the provisional duty imposed by the Central Government is withdrawn in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 18, the provisional duty already imposed and collected, if any, shall be refunded to the importer.

22. Margin of dumping, for exporters not originally investigated :—(1) If a product is subject to anti-dumping duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product of India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product.

(2) The Central Government shall not levy anti-dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule :

Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee from the importer if the designated authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of the initiation of the review.

23. Review :—(1) The designated authority shall, from time to time, review the need for the continued imposition of the anti-dumping duty and shall, if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for the continued imposition of such duty recommend to the Central Government for its withdrawal.

(2) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding twelve months from the date of initiation of such review.

(3) The provisions of rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 shall be mutatis mutandis applicable in the case of review.

24. Dumping causing injury to a third country :—

(1) The designated authority may initiate investigation into any dumping alleged to be taking place into India and causing injury to the domestic industry of any third country which is a member of the World Trade Organisation.

(2) The designated authority in such cases shall follow the procedures laid down in Article 14 of the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade, 1994, as contained in the Final Act of Uruguay Round Multilateral Trade Negotiations.

ANNEXURE I

(Sec rule B)

Principles governing the determination of Normal Value, Export Price and Margin of Dumping.

The designated authority while determining the normal value, export price and margin of dumping shall take into account inter alia, the following principles :—

1. The elements of costs referred to in the context of determination of normal value shall normally be determined on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, provided such records are in accordance with the generally accepted accounting principles of the exporting country, and such records, reasonably reflect the cost associated with production and sale of the article under consideration.

2. Sales of the like product in the domestic market of the exporting country or sales to a third country at prices below per unit (fixed and variable) costs of production plus administrative, selling and general costs may be treated as not being in the ordinary course of trade by reason of price. The designated authority may disregard these sales, in determining normal value, provided it has determined that :—

- (i) such sales are made within a reasonable period of time (not less than six months) in substantial quantities, i.e. when the weighted average selling price of the article is below the weighted average per unit costs or when the volume of the sales below per unit costs represents not less than twenty per cent of the volume sold in transactions under consideration, and
- (ii) such sales are at prices which do not provide for the recovery of all costs within a reasonable period of time. The said prices will be considered to provide for recovery of costs within a reasonable period of time if they are above weighted average per unit costs for the period of investigation, even though they might have been below per unit costs at the time of sale.

3. (i) The said authority in the course of investigation shall consider all available evidence on the proper allocation of costs, including that which is made available by the exporter or producer provided that such allocation has been historically utilised by

the exporter or producer, in relation to establishing appropriate amortization and depreciation periods and allowances for capital expenditure and other development costs.

(ii) unless already reflected in allocation of costs referred to in clause (1) and sub-clause (i) above, the designated authority, will also make appropriate adjustments for those non-recurring items of cost which benefit further and/or current production, or for circumstances in which costs during the period of investigation are affected by start up operation.

4. The amounts for administrative, selling and general costs and for profits as referred to in sub-section (1) of section 9-A of the Act, shall be based on actual data pertaining to production and sales in the ordinary course of trade, of the like article by the exporter or producer under investigation. When such amounts cannot be determined on this basis, the amounts may be determined on the basis of :—

- (i) the actual amounts incurred and realized by the exporter or producer in question, in respect of production and sales in the domestic market of the country of origin of the same general category of article ;
- (ii) the weighted average of the actual amounts incurred and realized by other exporters or producers subject to investigation in respect of production and sales of the like article in the domestic market of the country of origin ; or
- (iii) any other reasonable method, provided that the amount for profit so established shall not exceed the profit normally realized by the exporters or producers on sales of products of the same general category in the domestic market of the country of origin.

5. The designated authority, while arriving at a constructed export price, shall give due allowance for costs including duties and taxes, incurred between importation and resale and for profits.

6. (i) While arriving at margin of dumping, the designated authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at the ex-factory level, and in respect of sales made at as nearly as possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other difference which are demonstrated to affect price comparability.

(ii) In the cases where export price is a constructed price, the comparison shall be made only after establishing the normal value at equivalent level of trade.

(iii) When the comparison under this para requires a conversion of currencies, such conversion should be made by using the rate of exchange on the date of sale, provided that when a sale or foreign currency on forward markets is directly linked to the export sale involved the rate of exchange in the forward

sale shall be used. Fluctuations in exchange rates shall be ignored and in an investigation the exporters shall be given at least sixty days to have adjusted their export prices to reflect sustained movements in exchange rates during the period of investigation.

(iv) Subject to the provisions governing comparison in this paragraph, the existence of margin of dumping during the investigation phase shall normally be established on the basis of a comparison of a weighted average normal value and export prices on a transaction-to-transaction basis. A normal value established on a weighted average basis may be compared to prices of individual export transactions if it is found that a pattern of export prices which differ significantly among different purchasers regions or time periods, and if an explanation is provided as to why such differences cannot be taken into account appropriately by the use of a weighted average-to-weighted average or transaction-to-transaction comparison.

ANNEXURE-II

[See rule 9(2)]

PRINCIPLES FOR DETERMINATION OF INJURY

The designated authority while determining the injury or threat of material injury to domestic industry or material retardation of the establishment of such an industry, hereinafter referred to as "injury" and causal link between dumped imports and such injury, shall inter-alia, take following principles under consideration :—

- (i) A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.
- (ii) While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the designated authority shall consider whether there has been a significant price under cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred, to a significant degree.
- (iii) In cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the designated authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as percentage of export

price and the volume of the imports from each country is three per cent of the import of like article or where the export of individual countries less than three per cent, the imports collectively accounts for more than seven per cent of the import of like article and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

- (iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilisation of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
- (v) It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping as set forth in paragraphs (ii) and (iv) above, causing injury to the domestic industry. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of relevant evidence before the designated authority. The designated authority shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry.

(vi) The effect of the dumped imports shall be assessed in relation to the domestic production of the like article when available data permit the separate identification of that production on the basis of such criteria as the production process, producers' sales and profits. If such separate identification of that production is not possible, the effects of the dumped imports shall be assessed by the examination of the production of the narrowest group or range of products, which includes the like product, for which the necessary information can be provided.

(vii) A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the designated authority shall consider, inter alia, such factors as :

- (a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
- (b) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- (c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
- (d) inventories of the article being investigated.

[F. No. 525/2/94-Cus. (TU)]

S. M. BHATNAGAR, Under Secy.

